भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 354
02 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

तमिलनाडु में मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना

354. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में विशेषकर बंदरगाहों, लैंडिंग केंद्रों, शीत भंडारण सुविधाओं और प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या सहित मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना के विकास के लिए कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ग) सरकार द्वारा तमिलनाडु के दूरदराज और तटीय क्षेत्रों में छोटे और कारीगर मछुआरों को आधुनिक अवसंरचना, ऋण और तकनीकी सहायता तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा तमिलनाडु में स्थायी मत्स्यपालन पद्धतियों को बढ़ावा देने, मछली उत्पादन बढ़ाने और मछली तथा जलीय कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुँच में सुधार करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार तमिलनाडु में मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए कोई सुधार, योजना विस्तार या नई योजनाएँ आरम्भ करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और आधुनिकीकरण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। 9,558.91 करोड़ रुपए की लागत से 116 फिशिंग हार्बर और फिश लैंडिंग सेंटर्स को स्वीकृति दी गई है। यह आधुनिकीकरण देश भर में लॉजिस्टिक्स और मारकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से जुड़ा है। भारत की फिशरीज़ वैल्यू चेन में अभी 532 प्री-प्रोसेसिंग यूनिट, 230 हैंडलिंग सेंटर, 683 प्रोसेसिंग प्लांट, 6,410 कियोस्क, 202 रीटेल मारकेट और 21 होलसेल मारकेट शामिल हैं। कुल मिलाकर, इन सुविधाओं ने विगत पांच वर्षों में 3,254 करोड़ रुपए के कुल निवेश से फिश हैंडलिंग और वितरण को आधुनिक बनाया है।

उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, बायोफ्लोक, आरएएस, रेसवे और केज कल्चर सिस्टम जैसी 75,000 से अधिक आधुनिक उत्पादन इकाइयों को सहायता प्रदान की गई है और लगभग 34,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को जलीय कृषि के अंतर्गत लाया गया है। FIDF के तहत, 5,794.09 करोड़ रुपए के 132 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें 22 फिशिंग हार्बर और 24 लैंडिंग सेंटर शामिल हैं । फ़ंड को वित्तीय वर्ष 2025–26 तक बढ़ा दिया गया है और निजी संस्थाओं तथा सहकारी संस्थाओं के लिए 25% निवेश को कवर करने वाली एक ऋण गारंटी पद्धति के माध्यम से इसे सुदृढ़ किया गया है। ब्रूड स्टॉक और बीज की उपलब्धता को सुदृढ़ करने के लिए, 31 ब्रूड बैंक और 1,453 हैचरी का एक सुदृढ़ नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है, जबकि स्कैम्पी, ट्राउट, पर्ल स्पॉट और श्रिम्प जैसी वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के आनुवंशिक सुधार (जेनेटिक इंप्रूवमेंट) के लिए पहलें चल रही हैं। फिशरीज़ क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से पर्ल, ऑर्नामेंटल फिश, टूना और सीवीड जैसे क्षेत्रों में एकीकृत (इंटीग्रेटेड) उत्पादन और प्रोसेसिंग क्लस्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। तमिलनाडु में 682.6 करोड़ रुपए के निवेश से ग्यारह एकीकृत एक्वा पार्क और सीवीड प्रोसेसिंग और संबन्धित कृषि को सहायता प्रदान करने के लिए 127.71 करोड़ रुपए के निवेश से एक मल्टीपर्पस सीवीड पार्क शुरू किया जा रहा है ।

वर्तमान में, तमिलनाडु में फिशरीज़ और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के भाग के तौर पर 15 फिशिंग हार्बर, 148 फिश लैंडिंग सेंटर, 243 आइस प्लांट, 38 कोल्ड स्टोरेज और 60 प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए गए हैं।

(ख): विगत पांच वर्षों (2020-2025) के दौरान तमिलनाडु में मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 62 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 1094.8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, और तमिलनाडु सरकार को 797.23 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

(ग): भारत सरकार ने तमिलनाडु के दूरदराज और तटीय क्षेत्रों में छोटे पैमाने के और पारंपरिक मछुआरों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट और तकनीकी सहायता तक पहुंच की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे कि छोटे पैमाने के और परम्परागत मछुआरों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा, फिशिंग हार्बर, फिश लैंडिंग सेंटर, एक्वा पार्क, फिश मारकेट, प्रोसेसिंग यूनिट,कोल्ड स्टोरेज आदि जैसे फिशरीस इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास। इसके अलावा, विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थानों के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए तकनीकी सहायता के अलावा मछुआरों को कौशल और क्षमता विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

(घ): मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने तमिलनाडु में मत्स्यन के स्थाई (सस्टेनेबल) पद्धतियों को बढ़ावा देने, मत्स्य उत्पादन बढ़ाने और मत्स्य और एक्वाकल्चर उत्पादन के लिए मारकेट पहुँच को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे तमिलनाडु के तट पर आर्टिफिशियल रीफ लगाना, राज्य MFR एक्ट के तहत जाल के आकार के संबंध में रेगुलेशन लागू करना, नो फिशिंग ज़ोन, गियर पर रोक, विनाशकारी मत्स्यन विधियों पर प्रतिबंध आदि। इसके अलावा, पर्यावरण के अनुकूल वाले गिल नेट, लॉन्ग लाइन जैसी चुनिंदा फिशिंग गियर के उपयोग और देशी क्रॉफ्ट के मोटराईज़ेशन द्वारा डीप सी फिशिंग की ओर ट्रालिङ्ग को प्रोत्साहित करके समुद्री मात्स्यिकी में वैविध्यता को बढ़ावा दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु की प्रमुख नदियों में उन्नत फिंगरलिंग्स का स्टॉकिंग किया गया, पंचायत टैंकों में फिश सीड की स्टॉकिंग तथा मत्स्य किसानों को मत्स्य बीज एवं मत्स्यन उपकरण प्रदान किए गए, मत्स्य बाजारों की स्थापना एवं फिश कियोस्क, इन्सुलेटेड एवं रेफ्रिजेरेटेड वाहन, जीवित मत्स्य विक्रय यूनिट्स, आइस बॉक्स युक्त टू/थ्री व्हीलर के लिए सहायता प्रदान की गई, ताकि बाजार तक पहुंच को आसान बनाया जा सके और तमिलनाडु में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

(ड़): भारत सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकार से मिले प्रस्तावों के आधार पर मात्स्यिकी और जलीय कृषि संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से तमिलनाडु राज्य सरकार को सहायता प्रदान की है। तमिलनाडु राज्य सरकार को FIDF के तहत सबसे अधिक मात्स्यिकी और जलीय कृषि संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी गई है।

*****